The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 7 | July 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शैक्षिक स्थगन के सन्दर्भ में अध्ययन

डॉ शिव मगन

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, जे0 एस0 हिन्दू पी0 जी0 कॉलेज, अमरोहा

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16793371

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 21-07-2025

Published: 10-08-2025

Keywords:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शैक्षिक स्थगन, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा।

ABSTRACT

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिये अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना। भारत में समय-समय पर कई समितियाँ और नीतियाँ आई है जो हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का कार्य किया। इसी प्रकार हर्टांग समिति (1929) में अपव्यय एवं अवरोधन पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और इसे कम करने का प्रयास किया गया, अर्थात् शैक्षिक स्थगन को भी कम करने का प्रयास किया गया बच्चों में शैक्षिक स्थगन क्यों हो रहा है इस पर विचार किया गया। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देती है। नई शिक्षा नीति 2020 का यह प्रयास है कि बालकों में शैक्षिक स्थगन न हो अर्थात 'जीरो रिजेक्शन' पॉलिसी पर कार्य करती है। ताकि शिक्षा को सभी बालकों में सर्वसुलभ बनाया जा सके। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्यात्मक जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर की तार्किक और समस्या समाधान सम्बन्धी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक सामाजिक और भावात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। अतः निष्कर्ष स्वरूप में हम यह कह सकते है कि नई शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक स्थगन के कारणों को जानकर उसे समाधान करने का प्रयास करेगा।

परिचय:-

पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने के लिए, न्यायसंगत व न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा एवं इन

युवाओं को उच्चतर गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। वर्ष 2015 में भारत में अपनायें गये सतत विकास एजेन्डा-2030, (Sustainable Development Goal-2030) के लक्ष्य चार में परिलक्षित वैश्विक परिदृश्य में सम्पूर्ण विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य है। इसके लिये सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली पुर्नगठित करने की जरूरत होगी। रोजगारों की प्रकृति तथा वैश्विक परिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से बच्चों को सिखाने के साथ-साथ सतत सीखते रहने की कला सीखना भी जरूरी हो गया है। इसलिए शिक्षा में विषय-वस्तु को बढ़ाने के स्थान पर बच्चों को समस्या समाधान तथा तार्किक व रचनात्मक ढंग से सोचना सिखाने, विविध विषयों के बीच अन्तर्सम्बन्धों को देखने, नये ढंग से सोचने एवं नवीन जानकारी को नई व बदलती परिस्थितियों में उपयोग लाने पर जोर देना होगा। जरूरत है कि शिक्षण-प्रक्रिया शिक्षार्थी केन्द्रित हो; जिज्ञासा, खोज, अनुभव व संवाद के आधार पर संचालित हो; लचीली हो; समग्रता व समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली हो एवं रूचिपूर्ण हो। शिक्षा जीवन के सभी पक्षों व क्षमताओं को संतुलित विकास करने वाली होनी चाहिए। किसी भी शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य निःसंदेह ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार व कार्य करने में सक्षम हो, जिनमें करूणा व सहानुभूति, साहस व लचीलापन वैज्ञानिक चिन्तन व रचनात्मक कल्पनाशक्ति एवं नैतिक टिकाऊ आधार हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व 1929 ई0 में हर्टांग समिति आयी थी जिसमें उन्होंने अपव्यय व अवरोधन पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और इसे कम करने का प्रयास किया गया अर्थात् जो बच्चों में शैक्षिक स्थगन हो रहा था उन कारणों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास किया गया इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ड्राफ्ट आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देती है। नई शिक्षा नीति 2020 का यह प्रयास है कि बालकों में शैक्षिक स्थगन न हो अर्थात् शून्य अस्वीकृत (Zero rejection) पॉलिसी पर कार्य करती है ताकि शिक्षा को सभी बालकों में सर्वसुलभ बनाया जा सके।

अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है- **फिजूल खर्च।** शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग इसी अर्थ में होता है जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम (प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्च) में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किये बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते है। अपव्यय इसलिए कि बच्चों के प्रवेश लेने से पढ़ाई बीच में छोड़ने तक जो समय, शक्ति और धन का व्यय हुआ वह व्यर्थ चला जाता है। भारत में इस ओर सबसे पहले ध्यान प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में हर्टांग कमेटी (1929) में आकर्षित किया। **हर्टांग के अनुसार**-"अपव्यय से हमारा तात्पर्य बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही किसी कक्षा से हटा लेने से है।"

अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है- **रूकावट।** शिक्षा के क्षेत्र में भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते है। अवरोधन इसलिए कि इसमें किसी एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को उतने ही समय में पूरा करने में अवरोध होता है, छात्र के अध्ययन

क्रम में रूकावट आती है। समय, शक्ति और धन का अतिरिक्त व्यय होता है। **हर्टांग कमेटी के अनुसार**- "अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे का किसी निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है।"

स्थगन (Procrastination) लैटिन भाषा के प्रोक्रेस्टिनेयर (Procrastinare) से लिया गया है किसी भी कार्य में देरी, (विलम्ब), स्थगन एक सामान्य समस्या है। शैक्षिक स्थगन अन्य पर्याय शब्द है। जैसे-शैक्षिक शिथिलता, शैक्षिक विलम्ब, अध्ययन में टाल-मटोल आदि। शिथिलता एक ऐसा व्यवहार है जिसे किन्हीं क्रियाओं या कार्यों को परवर्ती समय के लिये स्थगन द्वारा परिलक्षित किया जाता है। शिथिलता के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी या वादों को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में तनाव, अपराध बोध, व्यक्तिगत उत्पादकता की हानि, संकट की पुष्टि और अन्य व्यक्तियों की असहमति का सामना करना पड़ सकता है। इस संयुक्त भावनाओं से शिथिलता को और प्रोत्साहन मिल सकता है। जब सामान्य क्रिया कलापों में बाधा उत्पन्न करने लगता है। दीर्घकालीन शिथिलता किसी अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक विकार एक संकेत हो सकता है। शिथिलता एक सतत् तथा दुर्बल करने वाला एक विकार पैदा कर सकती है। जिसके कारण अधिगम अक्षमता व मानसिक दौर्बल्य हो जाता है। जो शिक्षा में अरूचि को उत्पन्न करता है। जिससे छात्र अपने गृह कार्य करने में विलम्ब करता है। शैक्षिक स्थगन शिक्षक के भय द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। अतः विद्यालय का यह दायित्व है कि बालक के लिये भयमुक्त वातावरण बनाये। हमारे सम सामायिक समाज में व्यक्ति अक्सर किसी कार्य को करने के लिये टाल-मटोल करता है, अर्थात् कल कर लेगें। यही कार्य जब शिक्षा के क्षेत्र में बालक करता है तो इसे शैक्षिक स्थगन की श्रेणी में रखा जाता है जैसे जब शिक्षक बालक को गृह कार्य देते है तो बालक उस कार्य को अगले दिन के लिए टाल देते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की संरचनाः- 5+3+3+4

विद्यालयी शिक्षा (School Education)

सोपान (Stage)	बुनियादी सोपान (Foundation Stage)		उपक्रमात्मक सोपान (Prparatory Stage)	मध्यवर्ती सोपान (Middle Stage)	माध्यमिक सोपान (Secondary Stage
नामकरण (Nomenclature)	नामकरण तीन वर्षीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा।	दो वर्षीय निम्न प्राथमिक शिक्षा।	तीन वर्षीय उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 3 से 5 तक(	तीन वर्षीय मध्यवर्ती शिक्षा (कक्षा 6 से 8 तक(	चार वर्षीय माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12 तक(
आयु (Age)	3 वर्ष	6 वर्ष	8 वर्ष	11 वर्ष	14 वर्ष

उच्चतर शिक्षा (Higher Education)

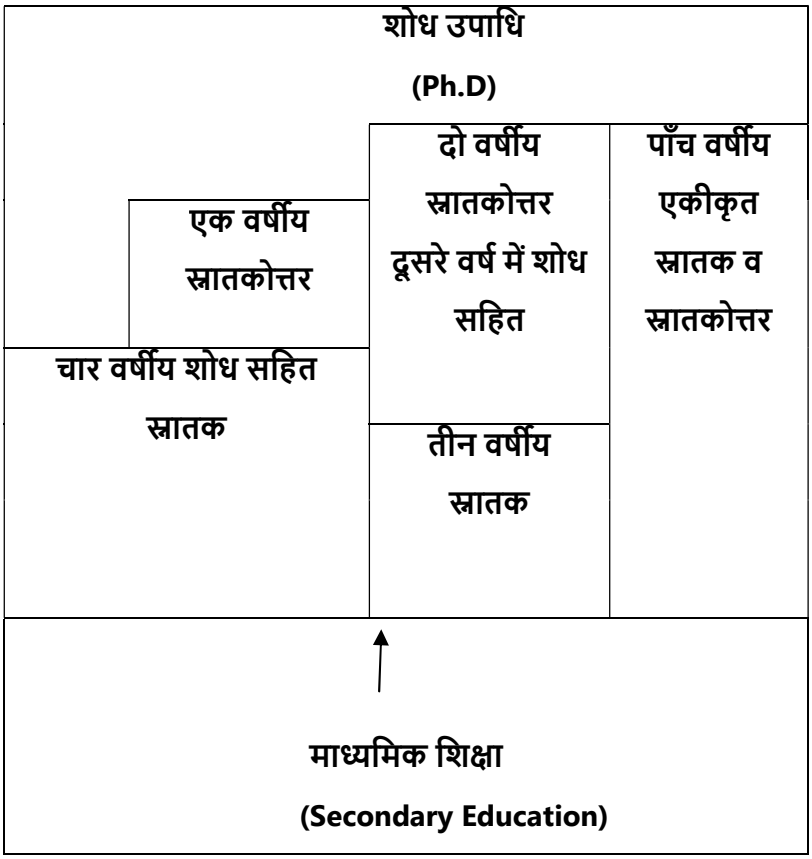

अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

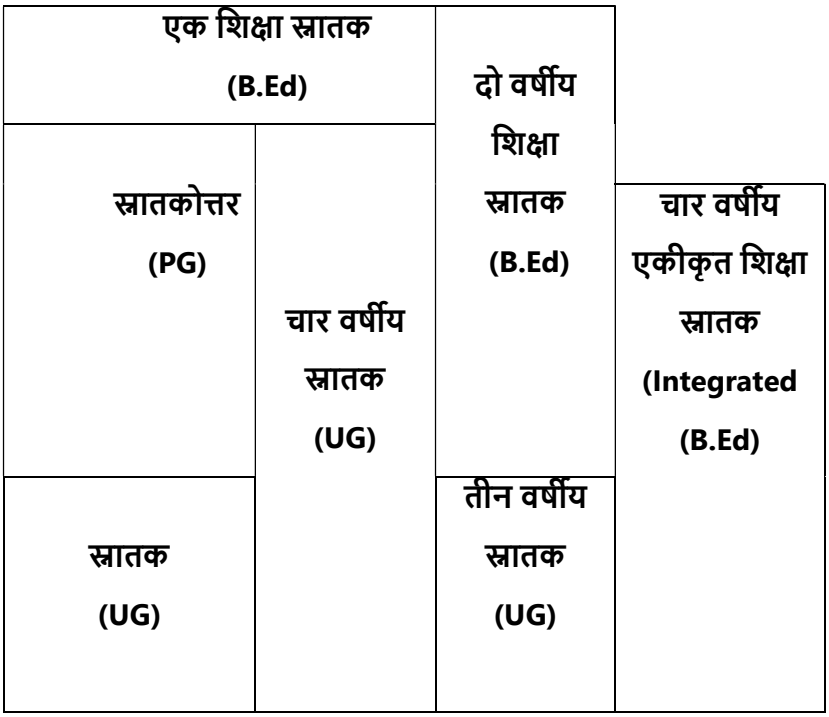

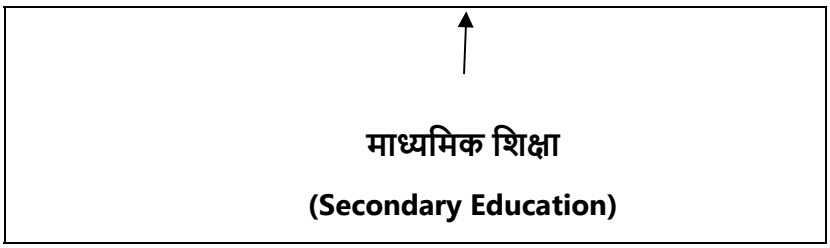

निष्कर्षः-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विवेचन से स्पष्ट है कि यह नीति काफी हद तक पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों से मिलती जुलती है। पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों में जहाँ पहुँच को बढ़ाने पर जोर दिया गया था वहीं इस नीति में पहुँच, समावेशन तथा गुणवत्ता जैसे पक्षों पर अधिक ध्यान देते हुये विभिन्न संकल्पों को निरूपित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाँच स्तम्भ पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहन और जवाबदेही। वस्तुतः वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों विशेषकर शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानव जीवन के सभी पक्षों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग व व्यापक घुसपैठ ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तनों को करने की आवश्यकता तथा पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। नई नीति एक ओर जहाँ अनेकानेक अमूलचूल परिवर्तन लाने की बात करती है वही तरह-तरह के भटकाव, उलझाव, व दोहराव में भी बुरी तरह ग्रसित है। कभी-कभी लगता है कि यह नीति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भावी चिन्तन तथा नीतिगत संकल्पों आदि का मिला जुला चिट्ठा है। निश्चित रूप से यह नीति बालकों के शैक्षिक स्थगन (Academic Procrastination) को कम करेगा।

सन्दर्भ सूचीः-

- पाठक, पी0डी0 (2012) भारतीय शिक्षा की सम समयिक समस्यायें, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।
- गुप्ता, एस0पी0 (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सरल परिचय, प्रयागराज, शारदा पुस्तक भवन।
- कौल, लोकेश)1998) शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिक हाउस प्रा0 लि0।
- सिंह, ए0के0 (2017) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, नई दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन।
- पाण्डेय, के0पी0 (2008), शैक्षिक अनुसंधान, वाराणसी, विश्व विद्यालय प्रकाशन।
- शिक्षा मंत्रालय 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार।
- सम सामायिक पत्र पत्रिकाएं।
- J. Burka and L.Yarn, "Procrastination: Why You Do it. What To Do About It, "New York: Peruses Books 1983.
- C.H Lay, "A more profile Analysis of Procrastination estimation: A search for types" Personality and Individual Differences, vol.8, pp. 705-714, 1987.